मेसर्स.गणेश सातारकर प्रकाशित

जापान का संविधान

ISBN: 978-81-999963-4-2

Author: - MR.GANESH SHRIRANG SATARKAR

LL.M

Advocate, Bombay High Court

M/s.Adv.Ganesh Shrirang Satarkar & Co.
Published By This Book
Email: ganeshnale0@gmail.com | adv.ganeshsatarkar@gmail.com
Mobile: +91 7066766607 | +91 9422422932

1. **BOOK TITLE : जापान का संविधान**
2. **LANGUAGE:** HINDHI
3. **ISBN: 978-81-999963-4-2**
4. **EDITION:** FIRST EDITION
5. **AUTHOR: Mr. GANESH SHRIRANG SATARKAR**
6. **PUBLISHER/ PUBLISHING AGENCY** :-
7. **M/s. K.K & ASSOCIATES.–** SHIVNERI, GAT NO 153, FARANDWADI, MANE MALA TAL PHALTAN, DIST - SATARA. MAHARSHTA, PIN 415523 INDIA
8. **CONTACT DETAILS:**
   MOBILE: +91 7066766607 **EMAIL:** GANESHNALE0@GMAIL.COM
9. **YEAR OF PUBLICATION:** 2026
10. **FORMAT:** SINGLE-COMPONENT RETAIL PRODUCT (BOOK)
11. **PRICE (IN INDIA):** ₹ 10 /- (**Printed and Published in India)**

COPYRIGHT & PUBLICATION STATEMENT

© 2026 **Mr. Ganesh Shrirang Satarkar (Nale)**
All rights reserved.
Disclaimer:
This publication is protected under applicable copyright laws. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, digitized, scanned, transmitted, copied, shared, sold, or circulated in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopying, recording, audio-visual, digital, or online—without the prior written permission of the author and the publisher, except for brief quotations permitted strictly for academic, educational, research, or review purposes This book has been authored with the sole objective of presenting research-based, educational, and informative content in a clear, responsible, and accessible manner for students, scholars, and general readers. There is no intention whatsoever to offend, defame, misrepresent, or harm the sentiments, beliefs, dignity, or rights of any individual, community, group, culture, religion, or institution. All references are included purely for scholarly discussion. Every effort has been made to ensure accuracy; however, inadvertent errors may occur. Readers are requested to inform the publisher for correction in future editions. Unauthorized reproduction or piracy is punishable under law.

BIOGRAPHY : ADV. GANESH SHRIRANG SATARKAR

Adv. Ganesh Shrirang Satarkar is an emerging legal scholar, researcher, and academic contributor working at the intersection of law, criminology, sociology, and digital governance. He is currently associated with the Central University of Haryana, where he is pursuing postgraduate research in sociology alongside his interdisciplinary work in legal studies.

He holds an LL.M. in Criminal Law, LL.B. (Special), and has qualified the UGC-NET in both Law and Criminology. His academic research focuses on criminal justice systems, cybercrime, artificial intelligence in law, media and crime, governance studies, and socio-legal research.

Adv.Ganesh has contributed to national and international academic platforms through research publications, conference papers, and interdisciplinary collaborations. His work explores emerging legal challenges in areas such as digital justice, cyber security, social justice, gender studies, and technological transformations in legal systems.

He is actively connected with several international academic and research platforms including ORCID, Web of Science, SSRN, Vidwan (INFLIBNET), Google Scholar, OSF, and Harvard Dataverse.

Author Bio Researcher Profiles :

1. ResearchIDs : rid131046
2. Orcid Id : https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8474-7432
3. ISNI : https://isni.org/isni/0000000529498911
4. Web of Science ResearcherIDOYE-6264-2025
5. Social science research network SSRN Author ID: 9293272
6. Vidwan Profile URL: https://vidwan.inflibnet.ac.in/profile/666713
7. Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=4MrvCEwAAAAJ
8. OSF ID : https://osf.io/cndj8/
9. harvard.edu : https://dataverse.harvard.edu/dataverse/GANESHSHRIRANGSATARKAR).
10 https://about.me/adv.ganeshsatarkar

Email: ganeshnale0@gmail.com | adv.ganeshsatarkar@gmail.com
Mobile: +91 7066766607 | +91 9422422932

ADV. GANESH SHRIRANG SATARKAR

CERTIFICATE

OF WORLD RECORD

Proudly Presented To

Ganesh Shrirang Satarkar

In recognition of the outstanding achievement of becoming the First Indian to Translate and Publish the Constitutions of All 54 African Countries into Hindi as Separate ISBN-Registered Books, demonstrating exceptional dedication, scholarly excellence, and a significant contribution to legal literature and linguistic accessibility, thereby establishing a distinguished and historic record of academic accomplishment.

We officially announce the above-mentioned candidate as a globally certified **"Inspiration World Record Holder"**.

The certificate was issued on 27th February, 2026.

INSPIRATION IS WHERE PASSION BECOMES LEGACY

CERTIFIED

Application No. IWR/2026/UR0173
Certificate No. IWR/2026/WRH0081
Issued By: Chief Adjudicator

ISO CERTIFIED

VISHWAGURU ARPANAM 2026

VIA2025/SS-VA2025AZ760-2025-170/09102025

2 025100 900010

ISO 9001:2015 Registration No: QT-56622/0925
Micro, Small, and Medium Enterprises Registration Number: 11-0093948
Trademark Registered Under the Act of "TRADE MARKS ACT, 1999"

© www.inspirationworldrecords.org

जापान का संविधान

जापान का संविधान (1946)

1. देश का नाम

Japan
देश का नाम: जापान

---

2. संविधान का नाम

संविधान का नाम: जापान का संविधान, 1946
(Constitution of Japan, 1946)

यह संविधान 3 मई 1947 से लागू हुआ। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोकतंत्र, शांति और मानव अधिकारों को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया।

---

3. संविधान के अध्याय (Chapters)

जापान के संविधान में कुल **11 अध्याय (Chapters)** और **103 अनुच्छेद (Articles)** हैं।

अध्याय संख्या	अध्याय का नाम	अनुच्छेद
प्रस्तावना	Preamble	—
अध्याय I	सम्राट (The Emperor)	अनुच्छेद 1–8
अध्याय II	युद्ध का त्याग (Renunciation of War)	अनुच्छेद 9
अध्याय III	जनता के अधिकार एवं कर्तव्य	अनुच्छेद 10–40
अध्याय IV	संसद (The Diet)	अनुच्छेद 41–64
अध्याय V	मंत्रिमंडल (The Cabinet)	अनुच्छेद 65–75
अध्याय VI	न्यायपालिका (Judiciary)	अनुच्छेद 76–82
अध्याय VII	वित्त (Finance)	अनुच्छेद 83–91
अध्याय VIII	स्थानीय स्वशासन	अनुच्छेद 92–95
अध्याय IX	संशोधन (Amendments)	अनुच्छेद 96
अध्याय X	सर्वोच्च कानून	अनुच्छेद 97–99
अध्याय XI	अनुपूरक प्रावधान	अनुच्छेद 100–103

---

4. संविधान के अनुच्छेद (Articles)

https://www.constituteproject.org/countries/Asia/Japan

अध्याय I – सम्राट (Articles 1–8)

- अनुच्छेद 1 – सम्राट राष्ट्र का प्रतीक होगा।
- अनुच्छेद 2 – राजसिंहासन वंशानुगत होगा।
- अनुच्छेद 3 – सम्राट के कार्य मंत्रिमंडल की सलाह से होंगे।
- अनुच्छेद 4 – सम्राट केवल संवैधानिक कार्य करेगा।
- अनुच्छेद 5 – रीजेंसी व्यवस्था।
- अनुच्छेद 6 – प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति।
- अनुच्छेद 7 – सम्राट के औपचारिक कार्य।
- अनुच्छेद 8 – शाही संपत्ति पर संसद का नियंत्रण।

संक्षिप्त व्याख्या

इस अध्याय में सम्राट को केवल प्रतीकात्मक प्रमुख बनाया गया है। वास्तविक शक्ति जनता और संसद के पास है।

अध्याय II – युद्ध का त्याग (Article 9)

- जापान युद्ध नहीं करेगा।
- सेना का उपयोग आक्रमण के लिए नहीं होगा।
- अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांति से हल किया जाएगा।

संक्षिप्त व्याख्या

यह अनुच्छेद जापान को विश्व के सबसे शांतिप्रिय राष्ट्रों में शामिल करता है।

अध्याय III – जनता के अधिकार एवं कर्तव्य (Articles 10–40)

मुख्य अधिकार:

- समानता का अधिकार
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- धर्म की स्वतंत्रता
- शिक्षा का अधिकार
- संपत्ति का अधिकार
- न्याय का अधिकार
- मतदान का अधिकार
- श्रमिक अधिकार

संक्षिप्त व्याख्या

यह अध्याय जापानी नागरिकों को व्यापक मौलिक अधिकार प्रदान करता है।

अध्याय IV – संसद (Articles 41–64)

- संसद सर्वोच्च विधायी संस्था है।
- द्विसदनीय संसद:
  - प्रतिनिधि सभा
  - पार्षद सभा
- कानून निर्माण का अधिकार संसद को है।

संक्षिप्त व्याख्या

जापान में संसदीय लोकतंत्र स्थापित किया गया है।

अध्याय V – मंत्रिमंडल (Articles 65–75)

- कार्यपालिका की शक्ति मंत्रिमंडल में निहित है।
- प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है।
- मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है।

संक्षिप्त व्याख्या

यह अध्याय लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व और संसदीय शासन प्रणाली को मजबूत करता है।

अध्याय VI – न्यायपालिका (Articles 76–82)

- न्यायपालिका स्वतंत्र होगी।
- सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च संस्था है।
- न्यायालय कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है।

संक्षिप्त व्याख्या

न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाकर नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की गई है।

अध्याय VII – वित्त (Articles 83–91)

- राष्ट्रीय वित्त पर संसद का नियंत्रण।
- कराधान केवल कानून द्वारा।

https://www.constituteproject.org/countries/Asia/Japan

- बजट संसद में प्रस्तुत होगा।

संक्षिप्त व्याख्या

यह अध्याय वित्तीय पारदर्शिता और संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

अध्याय VIII – स्थानीय स्वशासन (Articles 92–95)

- स्थानीय निकायों को अधिकार।
- स्थानीय प्रशासन में जनता की भागीदारी।

संक्षिप्त व्याख्या

यह अध्याय विकेंद्रीकरण और लोकतंत्र को मजबूत करता है।

अध्याय IX – संशोधन (Article 96)

- संविधान संशोधन संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से।
- जनता की स्वीकृति आवश्यक।

संक्षिप्त व्याख्या

संविधान संशोधन प्रक्रिया कठोर रखी गई है।

अध्याय X – सर्वोच्च कानून (Articles 97–99)

- संविधान सर्वोच्च कानून है।
- सभी अधिकारियों को संविधान का पालन करना होगा।

संक्षिप्त व्याख्या

यह अध्याय संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करता है।

अध्याय XI – अनुपूरक प्रावधान (Articles 100–103)

- संविधान लागू करने की प्रक्रियाएँ।
- संक्रमणकालीन व्यवस्थाएँ।

संक्षिप्त व्याख्या

यह अध्याय संविधान के क्रियान्वयन से संबंधित प्रावधान देता है।

---

5. जापान के संविधान का विस्तृत समग्र वर्णन (लगभग 5000 शब्द)

प्रस्तावना

जापान का संविधान आधुनिक विश्व के सबसे महत्वपूर्ण संविधानों में से एक माना जाता है। यह संविधान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तैयार किया गया। युद्ध में हार के बाद जापान को एक नई राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई। पुराने संविधान में सम्राट के पास अत्यधिक शक्तियाँ थीं, लेकिन 1946 के संविधान ने लोकतंत्र, मानव अधिकार और शांति को सर्वोच्च महत्व दिया।

इस संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जनता को संप्रभुता का स्रोत माना गया है। पहले सम्राट सर्वोच्च था, लेकिन नए संविधान में जनता सर्वोच्च बनी। संविधान ने स्पष्ट किया कि सरकार जनता के लिए कार्य करेगी।

संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने आक्रामक सैन्य नीति अपनाई। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया। इसके बाद मित्र राष्ट्रों के प्रभाव में एक नया संविधान बनाया गया।

इस संविधान का मुख्य उद्देश्य था:

1. सैन्यवाद समाप्त करना।
2. लोकतंत्र स्थापित करना।
3. नागरिक स्वतंत्रता बढ़ाना।
4. शांति बनाए रखना।

सम्राट की स्थिति

जापान में सम्राट को राष्ट्र का प्रतीक माना गया है। संविधान के अनुसार सम्राट केवल औपचारिक प्रमुख है। वह सरकार नहीं चलाता। वास्तविक शक्ति संसद और मंत्रिमंडल के पास है।

सम्राट के कार्य:

- संसद बुलाना
- प्रधानमंत्री की नियुक्ति
- विदेशी राजदूतों का स्वागत

https://www.constituteproject.org/countries/Asia/Japan

- औपचारिक समारोह करना

इस व्यवस्था ने जापान को संवैधानिक राजतंत्र बनाया।

युद्ध का त्याग – अनुच्छेद 9

अनुच्छेद 9 जापान के संविधान की सबसे प्रसिद्ध विशेषता है। इसमें कहा गया है कि जापान युद्ध नहीं करेगा और सैन्य शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा।

यह विश्व में शांति का अनूठा उदाहरण है। इसी कारण जापान को शांतिवादी राष्ट्र कहा जाता है। हालांकि सुरक्षा के लिए जापान ने "Self Defense Forces" बनाई हैं।

मौलिक अधिकार

संविधान ने नागरिकों को अनेक अधिकार दिए हैं:

1. समानता का अधिकार

सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।

2. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

प्रेस, भाषण और विचार की स्वतंत्रता दी गई है।

3. धर्म की स्वतंत्रता

राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा।

4. शिक्षा का अधिकार

सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा।

5. श्रमिक अधिकार

मजदूर संगठन बना सकते हैं और सामूहिक सौदेबाजी कर सकते हैं।

6. न्यायिक अधिकार

किसी व्यक्ति को बिना उचित प्रक्रिया के दंड नहीं दिया जा सकता।

संसद व्यवस्था

जापान की संसद को “Diet” कहा जाता है।

संसद के दो सदन

1. प्रतिनिधि सभा
2. पार्षद सभा

संसद के कार्य

- कानून बनाना
- बजट पारित करना
- प्रधानमंत्री चुनना
- सरकार पर नियंत्रण रखना

प्रतिनिधि सभा अधिक शक्तिशाली मानी जाती है।

मंत्रिमंडल

प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है।

प्रधानमंत्री के कार्य:

- मंत्रियों की नियुक्ति
- प्रशासन चलाना
- विदेश नीति निर्धारित करना
- संसद में बिल प्रस्तुत करना

न्यायपालिका

जापान की न्यायपालिका स्वतंत्र है।

सर्वोच्च न्यायालय

यह सबसे बड़ा न्यायालय है।

इसके कार्य:

- संविधान की व्याख्या
- कानूनों की वैधता जांचना
- नागरिक अधिकारों की रक्षा

https://www.constituteproject.org/countries/Asia/Japan

न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वित्तीय व्यवस्था

संविधान के अनुसार राष्ट्रीय धन पर संसद का नियंत्रण होगा।

मुख्य बातें:

- कर केवल कानून से लगाए जाएंगे।
- बजट संसद में पेश होगा।
- सरकारी खर्च की जांच होगी।

स्थानीय स्वशासन

स्थानीय निकायों को अधिकार दिए गए हैं ताकि प्रशासन जनता के करीब हो।

स्थानीय निकाय:

- नगरपालिका
- प्रीफेक्चर

इससे लोकतंत्र मजबूत होता है।

संविधान संशोधन

संविधान संशोधन आसान नहीं है।

प्रक्रिया:

1. संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत।
2. जनता की स्वीकृति।

इससे संविधान की स्थिरता बनी रहती है।

संविधान की विशेषताएँ

1. लोकतांत्रिक संविधान

जनता सर्वोच्च है।

2. शांतिवादी संविधान

युद्ध का त्याग।

3. मानव अधिकारों की सुरक्षा

व्यापक मौलिक अधिकार।

4. स्वतंत्र न्यायपालिका

न्यायपालिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण नहीं।

5. संसदीय शासन प्रणाली

प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी।

जापान के संविधान का महत्व

यह संविधान जापान के पुनर्निर्माण का आधार बना। युद्धग्रस्त जापान आज विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था है। संविधान ने स्थिर लोकतंत्र और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आलोचनाएँ

कुछ लोग कहते हैं:

- अनुच्छेद 9 के कारण जापान कमजोर रक्षा नीति रखता है।
- संविधान में अमेरिकी प्रभाव अधिक था।
- संशोधन प्रक्रिया बहुत कठिन है।

फिर भी यह संविधान विश्व के सबसे सफल लोकतांत्रिक संविधानों में गिना जाता है।

निष्कर्ष

जापान का संविधान आधुनिक लोकतंत्र, शांति और मानव अधिकारों का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसने जापान को सैन्यवादी राष्ट्र से लोकतांत्रिक और शांतिप्रिय राष्ट्र में बदल दिया। संविधान में जनता की

संप्रभुता, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार और संसदीय शासन जैसी विशेषताएँ इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती हैं।

यह संविधान केवल जापान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति और लोकतंत्र का प्रेरणास्रोत है।

https://www.constituteproject.org/countries/Asia/Japan

M/s.Adv.Ganesh Shrirang Satarkar & Co.
Published By This Book

THE END

Email: ganeshnale0@gmail.com | adv.ganeshsatarkar@gmail.com
Mobile: +91 7066766607 | +91 9422422932